17 MARCH 2012 IIA IN NEWS

THE TIMES OF INDIA 17 MARCH 2012 LUCKNOW

Budget draws lots of brickbats, and a few bouquets as well

IIA, Banking Sector Call It Lacklustre;

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Reactions to the Union Budget remained tepid on Friday, with pockets of the Indian industry maintaining that not enough was done to push growth. The Indian Industry Association (IIA), the apex body of micro, small and medium scale enterprises (MSMEs), said it was looking to see if Union finance minister Pranab Mukherjee would promise much to the 2.6 crore MSMEs in India. Only three announcements related to the MSME sector were made; at least two of which had already been announced earlier.

Reacting to the budget, IIA general secretary Manish Goel said the budget would not be able to control inflation. Making way for Rs 5,000 crore for SMEs under the venture fund head was also not enough, he said. "An increase in income tax exemption limit from Rs 1.8 lakh to Rs 2 lakh is an eyewash because it will only offset the increase in inflation over the past one year," he said.

IIA former president Anil Gupta also said the sector was expecting reforms in taxation laws, the implementation of direct taxes code (DTC) and a definite roadmap for implementation of goods and services tax (GST), for instance. Though the FM expressed his intention to implement both, there was no definite roadmap. The budget's inability to impress was also attributed by many to a 'weak government' at the Centre. Another former president of IIA, G C Chaturvedi said the budget was a weak and safe one. He also said it was a negative budget.

"The budget has very little for the small and medium scale industries. We hoped that the finance minister will make adequate arrangements for infrastructural growth of the sector. There has been an urgent need for a mechanism of technology transfer that benefits the industry.

ANIL GUPTA | INDUSTRIALIST

राष्ट्रीय सहारा 17 मार्च 2012

लघु उद्योगों को निराश किया : लघु उद्योगों के संगठन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के पूर्व अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2012-13

के बजट में लघु उद्योगों के लिए कुछ खास नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी और डीटीसी के लिए कोई समयसीमा तय न होने से सुधारों पर ग्रहण सा लगता दिख रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि यह कमजोर सरकार का सुरक्षित बजट है। बजट में एमएसएमई के लिए 5000 करोड़ रुपये के 'इंडिया अपार्च्युनिटी वेंचर फंड' के गठन की जो सिफारिश की गयी है उसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आईआईए के महासचिव मनीष गोयल ने कहा कि बजट में महंगाई नियंत्रण के लिए कोई उपाय नहीं किये गये हैं। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संजय कौल ने कहा कि आबकारी एवं सेवा क्षेत्रों में टैक्स रेट जीएसटी के नाम पर 12 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है एवं सेस भी बढ़ा दिया है जिससे कुल टैक्स रेट में 2.5 फीसद की वृद्धि हो गयी है। इससे महंगाई बढ़ेगी और भारतीय उत्पाद एवं सेवाएं आयातित सामान एवं सेवाओं की अपेक्षा महंगे हो जाएंगे।

युनाइटिड भारत 17 मार्च 2012

लघु उद्योग के लिए बजट निराशाजनक

इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा बजट पर चर्चा करते हुए एवं विश्लेषण करते हुए कहा गया कि यह बजट महंगाई पर नियंत्रण नही कर सकेगा एवं एवम सरकार के लिए हेवी क्वालिटी से सम्बन्धित अपनी घोषणाओं विशेष कर कृषि से सम्बन्धित को पूरा करना कठिन हो जाएगा। इस बजट पर मनीष गोयल, अनिल गुप्ता, संजय कॉल आदि ने विचार रखें।

17 मार्च 2012

अमर उजाला

इन्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एकेगुप्ता ने कहा कि यह कमजोर सरकार का कमजोर बजट है। इसमें लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कुछ नहीं है। विनिर्माण विकास को बढ़ावा देने केलिए बजट में कोई प्राविधान नहीं है। जो सुधार अपेक्षित थे, वह इस बजट में दिखायी नहीं पड़े। नई संभावनाओं पर कुछ बजट केप्राविधान किए गये हैं पर उससे व्यवहारिक तौर पर कितना फायदा मिलेगा यह देखना होगा।

डेलीन्यूज 17 मार्च 2012

कमजोर सरकार का कमजोर बजट

लखनऊ (डीएनएन)। एमएसएमई एक्सचेन्ज की स्थापना और एमएसएमई क्षेत्र से 20 फीसदी खरीद की घोषणाएं काफी पहले की जा चुकी हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। आईआईए के महासचिव मनीष गोयल ने कहा कि यह बजट महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकेगा। सरकार के लिए से सम्बन्धित अपनी घोषणाओं विशेष कर कृषि से सम्बन्धित को पूरा करना कठिन हो जाएगा। इस के अतिरिक्त एसएमई के लिए केवल 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और वह भी वैन्चर फंड के लिए जिस तक बहुत कम लोगों की पहुंच है।

• आईआईए ने किया बजट चर्चा एवं विश्लेषण सत्र का आयोजन

इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) द्वारा बजट चर्चा एवं विश्लेषण सत्र का आयोजन शुक्रवार को आईआईए भवन गोमतीनगर में किया गया। जिसमें आईआईए के वरिष्ठ पदाधिकारी एवमं उद्यमिओं ने भाग लिया। आईआईए वित्त मन्त्री के भाषण में विशेषत: देश के 2.6 करोड़ एमएसएमई को मिलने वाले लाभों को खोज रहे थे। परन्तु उनका इन्तजार ही रह गया। उनकी निराशा का कारण यह था कि वित्त मंत्री ने सूक्ष्म लघु एवंम् मध्यम उद्योगों के लिए तीन घोषणाएं की। 5000 करोड़ रुपए का एमएसएमई एक्सचेन्ज की स्थापना एवं इस क्षेत्र से 20 फीसदी खरीद। आईआईए के पूर्व अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि हम टेक्सेसन लॉ में कुछ रिफॉर्म की अपेक्षा कर रहे थे जैसे कि डायरेक्ट टैक्स कोड का क्रियानवन एवमं जीएसटी का रोड मैप। वित्र मंत्री ने क्रियांवयन का रोड मैप नहीं दिया। जब वैट शुरू हुआ था तब यह कहा गया था कि सीएसटी खत्म कर दिया जाएगा तथा एक यूनीफॉर्म टैक्स रेट लागू किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आईआईए के पूर्व अध्यक्ष संजय कॉलने कहा कि आबकारी एवं सेवा क्षेत्रों में टैक्स रेट जीएसटी के नाम पर 12 फीसदी बढ़ा दिया गया है। सेस भी बढ़ा दिया है जिससे कि कुल टैक्स रेट में 2.5 फीसदी की अवधि हो गई है। इस प्रकार महंगाई में बढ़ोत्तरी होगी, उत्पादन कम होगा, आयातित सामान एवं सेवाओं की अपेक्षा महंगे हो जाएंगे तथा उद्योग घाटे में जाएंगे। पूर्व अध्यक्ष जी.सी. चतुर्वेदी ने कहा कि यह कमजोर सरकार का कमजोर बजट है। इस में इकोनॉमी के विकास की कोई सम्भावना नहीं है। रजत मेहरा ने कहा कि इस सरकार के अन्तर्गत इकोनॉमिक रिफॉर्मस रुक गए हैं।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने भी आयोजित की बजट पर परिचर्चा — हिन्दुस्तान

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीसी वर्मा का कहना है कि वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों के लिए कोई खास घोषणा नहीं की है। हां नई बोतल में पुरानी शराब जरूर पेश की है। मसलन वित्तमंत्री ने सरकारी उद्योगों को एमएसएमई से 20 प्रतिशत सामान खरीदने की अनिवार्यता को लागू होना चाहिए, यह घोषणा तो पिछले बजट में ही हो चुकी है। इसके अलावा एसएमई एक्सचेंज खोले जाने की बात कही गई है जबकि हाल ही बीएसई का एसएमई एक्सचेंज लांच हो चुका है। एमएसएमई के लिए सिडबी के सहयोग से 5000 करोड़ का इंडिया अपॉरच्युनिटी फंड की घोषणा का लाभ देश के सूक्ष्म उद्योगों को मिलना सपना होगा क्योंकि सिर्फ प्रदेश में ही 31 लाख एमएसएमई हैं। इसके अलावा डीटीसी (डायरेक्ट टैक्स कोड), सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में की गई बढ़ोतरी से आम क्या खास की भी कमर टूट जाएगी। सेस और अन्य टैक्स मिलाकर करीब ढाई प्रतिशत ज्यादा सर्विस टैक्स चुकाना होगा।

लखनऊ, 17 मार्च 2012 — राष्ट्रीय जागरण

बजट से उद्योग जगत मायूस

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने इसे कमजोर सरकार का कमजोर बजट करार दिया है। उनका कहना है कि विनिर्माण को बढ़ावा देने के मसले पर बजट खामोश है। बहुप्रतीक्षित गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को अब जहां अगस्त तक टाल दिया गया है, वहीं प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू करने के लिए भी कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है। बजट में 5000 करोड़ रुपये के इंडिया अपार्च्यूनिटीज वेंचर फंड को उन्होंने छोटे और मझोले उद्योगों के लिए झुनझुना बताया, यह कहकर कि एमएसएमई सेक्टर को व्यावहारिक तौर पर इसका लाभ नहीं मिलने वाला।

---

the pioneer

LUCKNOW SATURDAY | MARCH 17, 2012

Industry's thumbs down to Budget

MOHIB KHAN ■ LUCKNOW

Industry people on Friday trashed the Union Budget, saying it had nothing in the name of economic reforms.

DS Verma, executive director of Indian Industries Association (IIA), said IIA members and officials were disappointed because the Finance Minister made three announcements related to micro, small and medium enterprises (MSMEs), including Rs 5000 crore India opportunity venture fund, launch of small and medium enterprise (SMEs) exchanges and 20 per cent purchases from MSMEs.

"Interestingly, two out of the three announcements — SME exchanges and 20 per cent purchases — had been made much before the Budget and there is absolutely nothing new in it. The decision of 20 per cent purchases was taken by the PM's Task Force in 2010 and it has already been cleared by the Cabinet and SME Exchange has also been launched now," he pointed out.

Reacting to the Budget, IIA general secretary Manish Goel said the Budget would not be able to control inflation and it would be difficult for the government to fulfill its promises regarding the heavy outlay, especially for the agriculture sector. He further said that there was a provision of only Rs 5000 crore for SMEs and that too for venture fund, which could be accessed by very few. "The increase in income tax exemption limit from is an eyewash because it will highly offset the increase in inflation within the past one year," he noted.

Experts having a discussion on the Union Budget in Lucknow on Friday

Anil Gupta, former president of IIA, said they expected some reform process in taxation law such as implementation of direct taxes code (DTC) and definite roadmap for implementation of GST. "On both the accounts, the FM merely expressed his intention without definite [illegible] roadmap. When VAT was implemented, it was promised that CST would be phased out and uniform rate of tax would be implement, but the promises were yet to be fulfilled," he highlighted.

Sanjay Kaul, former president IIA and chairman of taxation working group said in the name of GST, the rate of tax for excise and services had been increased to 12 per cent and cess had also been increased, giving a net effect of about 2.5 per cent increase in the rate of tax.

"With this one stroke, the Budget has hit the manufacturing and service sectors badly. With this increase, inflation is bound to go up. Production will decrease, Indian products and services will become non-competitive and industrial sickness will also increase. It will be difficult for the RBI also to soften the rate of interest. Therefore, the overall cost of input will go up and the industry will go down," he said.

GC Chaturvedi, another former president of IIA said it was a weak but safe budget.

Dr Upendra Kumar, MD, UPTEC, however, appreciated the announcements regarding support for skill development and 23 per cent increase in the Prime Minister's Employment Guarantee Programme.

Rajat Mehra, member CEC, IIA, said under this government, all the economic reforms were held up, may be due to its political compulsions.

बजट परिचर्चा में भाग लेते इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्य — पायनियर — 17मार्च 2012

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिऐशन (आईआईए) के अनिल गुप्ता ने कहा कि छोटे व मझोले उद्योगों को उम्मीद थी कि इस बजट में उन्हें कोई दिशा मिलेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बजट में ऑपचुर्निटी वेंचर फंड स्थापित करने के नाम पर पांच हजार करोड़ के फंड की बात कही गयी है लेकिन इससे डायरेक्ट एमएसएमई को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। एक्साइज और सार्विस टैक्स म बहुत चीजों के आ जाने से वे सब महंगी हो जायेंगी।